दस साल का हिसाब किताब

रिपोर्ट कार्ड 2014-24

एनपीए + राइट ऑफ + विल्फुल डिफॉल्टर्स

लोकतंत्र का सार यह है कि हम सरकारों को उनके दावों और वादों के हिसाब से जवाबदेह बनाएं। लेकिन हाल के वर्षों में सबसे बड़ी क्षति जवाबदेही के विचार को पहुंची है। मीडिया द्वारा विभाजनकारी और अंधराष्ट्रवादी सामग्री का प्रसार, सामूहिक भूलने की बीमारी को बढ़ावा देता है। यह रिपोर्ट कार्ड (हालांकि निर्णायक नहीं) फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो वित्तीय और आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन के कुछ दावों और उनकी वास्तविकता पर नज़र डालने और उजागर करने का एक प्रयास है।

फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया - फैन इंडिया

दावे

पिछले कुछ वर्षों में एनपीए में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इसके बढ़ने का सिलसिला जारी है। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए कम करने के लिए बीजेपी जरूरी कदम उठाएगी: बीजेपी का 2014 का चुनावी घोषणापत्र

01

02

प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पहले हजारों करोड़ रुपये के घाटे और एनपीए के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब वे रिकॉर्ड मुनाफे के लिए जाने जाते हैं।

उदाहरण के लिए, 2018 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि NDA राजकाल मे बैंकों ने उन पार्टियों को ऋण नहीं दिया, जो बाद में भुगतान में चूक गए। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, 'नामदारों के कहने पर दिए गए कर्ज का एक-एक पैसा वसूल किया जाएगा।'

03

04

सात साल पहले एक साक्षात्कार में, मोदी ने कहा था कि वह जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों को कानून का स्वाद चखाएंगे, जो बड़े कॉर्पोरेट ऋणों पर चूक करके विदेश भाग जाते हैं। उन्होंने कहा, "जनता को यकीन है कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वह नरेंद्र मोदी हैं, " "और मैं यह जरूर करूंगा।"

पीएम मोदी ने हाल ही में एक रोजगार मेले में कहा था, "यूपीए गठबंधन सरकार ने घोटालों से बैंकिंग क्षेत्र को नष्ट कर दिया, जबकि मेरी सरकार ने इसकी वित्तीय स्थिति को बहाल किया है... फोन बैंकिंग, जहां शक्तिशाली लोगों के फोन कॉल पर ऋण वितरित किए जाते हैं, बंद हो गई है"

05

वास्तविकता

- हालाँकि आंकड़ों से पता चलता है कि 2014-15 के स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, यानी सरकारी बैंकों में ग्रॉस ऍनपीऐ का संचयन में **1.6** गुना वृद्धि हुई है, जो मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल के दौरान 54 लाख करोड़ है।

- तो, "बैंकिंग चमत्कार" केवल राइट-ऑफ़ नामक जादू की छड़ी का प्रभाव है। 2014-2023 तक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान बैंकों ने 14.56 लाख करोड़ रुपये को बट्टेखाते में डाला है, जहां बट्टे खाते में डालने के मूल्यों में 2015 की तुलना में लगभग 3 गुना से अधिक की वृद्धि देखी गई। बट्टे खाते में डालने का आंकड़ा **2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार का कुल खर्च से 2.5 गुना अधिक है।**

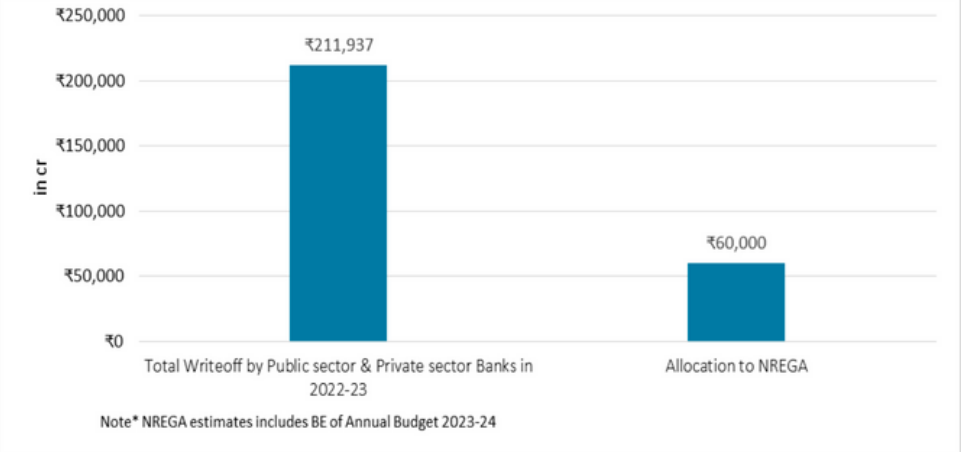

2022-23 में बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गयी पूँजी मनरेगा के लिए आवंटन से *3.5* गुना ज़्यादा है

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वार्षिक राइट-ऑफ राशि 2013 की तुलना में 2023 तक **17 गुना** बढ़ गई है और 7,187 करोड़ से 1.27 लाख करोड़ हो गई है!
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले 10 वर्षों में 2023 तक लगभग **3 लाख करोड़ रुपये** का सबसे अधिक संचयी रिटर्न दिया है।
- निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वार्षिक बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि 2013 की तुलना में 2023 तक **20 गुना** बढ़ गई है। 4115 करोड़ से लगभग 84 हजार करोड़ हो गई है!
- बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से वसूली 8% से बढ़कर 19% हो गई है, हालांकि, 2017-18 से 2021-22 तक विभिन्न चैनलों के माध्यम से बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से कुल वसूली केवल 14% है, जो दर्शाता है कि बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से वसूली दर बहुत मामूली है ।

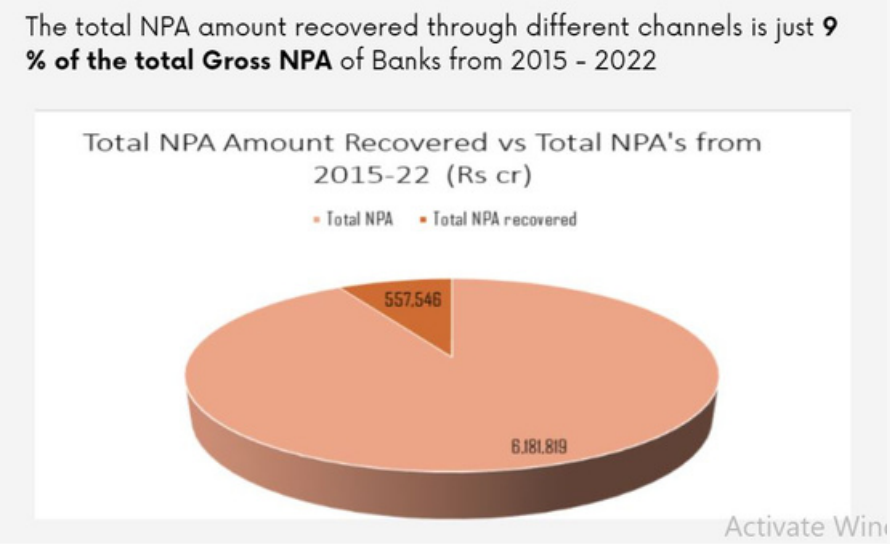

विलफुल डिफॉल्टर कौन है ?

विलफुल डिफॉल्टर वह उधारकर्ता होता है जो भुगतान करने की क्षमता होने के बावजूद ऋण चुकाने से इंकार कर देता है।

धोखेबाज़ कौन है ?

धोखेबाज वह होता है जो जानबूझकर गलत दस्तावेजों/ जानकारी के साथ बैंक को धोखा देता है और पैसे का दुरुपयोग करता है।

- जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले मामलों की संख्या 2014 की तुलना में लगभग 1.6 गुना बढ़ गई है, नवंबर 2023 तक जानबूझकर 25 लाख और उससे अधिक की राशि डिफॉल्ट करने वाले खातों के **9,249** मामले 1,96,930 करोड़ हैं।
- मेहुल चोकसी, ऋषि अग्रवाल और अन्य सहित शीर्ष 50 विलफुल डिफॉल्टरों पर लगभग 87 हजार करोड़ रुपये का बकाया है।

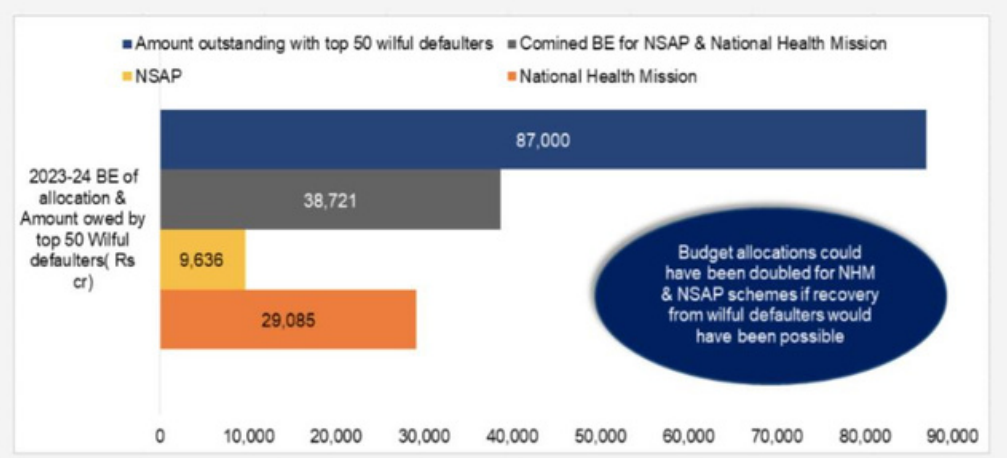

- आरबीआई ने हाल ही में ऐसे देनदारों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जान बूझकर चूक करने वालों या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत लोगों के लिए "समझौता निपटान" या "तकनीकी बट्टे खाते में डालने" की भी अनुमति दी है। निःसंदेह सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक यूनियनों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। इस तरह के निर्देश कॉर्पोरेट डिफॉल्टरों और धोखेबाजों को निपटान का आनंद लेने और फिर से उधार लेने की अनुमति देता हैं।

लेनदारों के सुपर सैलून

- एनसीएलटी प्रक्रिया जिसकी परिकल्पना बढ़ते एनपीए से निपटने के लिए एक तंत्र के रूप में की गई थी, उसे बड़े कटौती के माध्यम से कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने वाली प्रक्रिया में बदल दिया गया है। हेयरकट्स को कंपनियों के खराब ऋणों या तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर बैंकों द्वारा बैंकों द्वारा स्वेछा से वहन किये नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है। जब कोई बैंक 'हेयरकट' लेता है, तो इसका मतलब है कि वह किसी विशेष ऋण खाते में देय राशि से कम स्वीकार करता है।
- इनमें से कुछ ऐसे थे जैसे इलेक्ट्रोस्टील को 60% कटौती के बाद बेच दिया गया था और वेदांता द्वारा इसकी कीमत से 40% पर खरीदा गया था। आलोक इंडस्ट्रीज को 83% की कटौती मिली। रिलायंस ने इसे इसके मूल मूल्य के 17% पर खरीदा! उदाहरण के लिए, हाल ही में, एनसीएलटी ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली आरकॉम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) के संबंध में एक समाधान योजना को मंजूरी दे दी, जिसमें देनदारों से कुल 49668 करोड़ रुपये का दावा था। एनसीएलटी ने 47251 करोड़ रुपये के एवज में केवल रु. 455.92 करोड़ का निपटान को स्वीकार किया जो कर्ज का 0.92% है।
- आरपीजी एंटरप्राइज के अध्यक्ष हर्ष गोयनका ने कहा है, “प्रमोटर अपनी पूँजी किनारे रख लेते हैं, कंपनी के दाग साफ़ करवाने धुलाई के लिए ले जाते हैं, बैंकों और एनसीएलटी से 80% से 90% की छूट प्राप्त करते हैं। यह शहर में नया खेल है"।
- इस तरह के बड़े पैमाने पर हेअरकट, या ऋण माफी, बड़े पैमाने पर खराब ऋणों को संबोधित करने के लिए पीएसबी द्वारा बड़े पैमाने पर ऋण माफ करने के अतिरिक्त है, जो जनता की जमापूंजी से वित्त पोषित होते हैं। संसदीय पैनल ने वास्तव में सिफारिश की थी कि "हेअरकट की मात्रा के लिए एक बेंचमार्क होना अनिवार्य है" जो वैश्विक मानकों के बराबर हो।

- बकाएदारों पर सरकार के रिकॉर्ड की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए, यह ध्यान देने योग्य है कि इस साल 30 नवंबर तक 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऋण पर चूक करने वाले लोगों के लिए दायर मुकदमों की कुल **संख्या 23,707** है। इनका कुल बकाया **5,63,850 करोड़ रुपये** है।

- बैंक धोखाधड़ी में यह प्रवृत्ति स्पष्ट है। वे 2005-'14 की अवधि में 34,993 करोड़ रुपये से लगभग 17 गुना बढ़ कर 2015-'23 की अवधि में **5.89 लाख करोड़** रुपये हो गए। यह लगभग 17 गुना वृद्धि है।

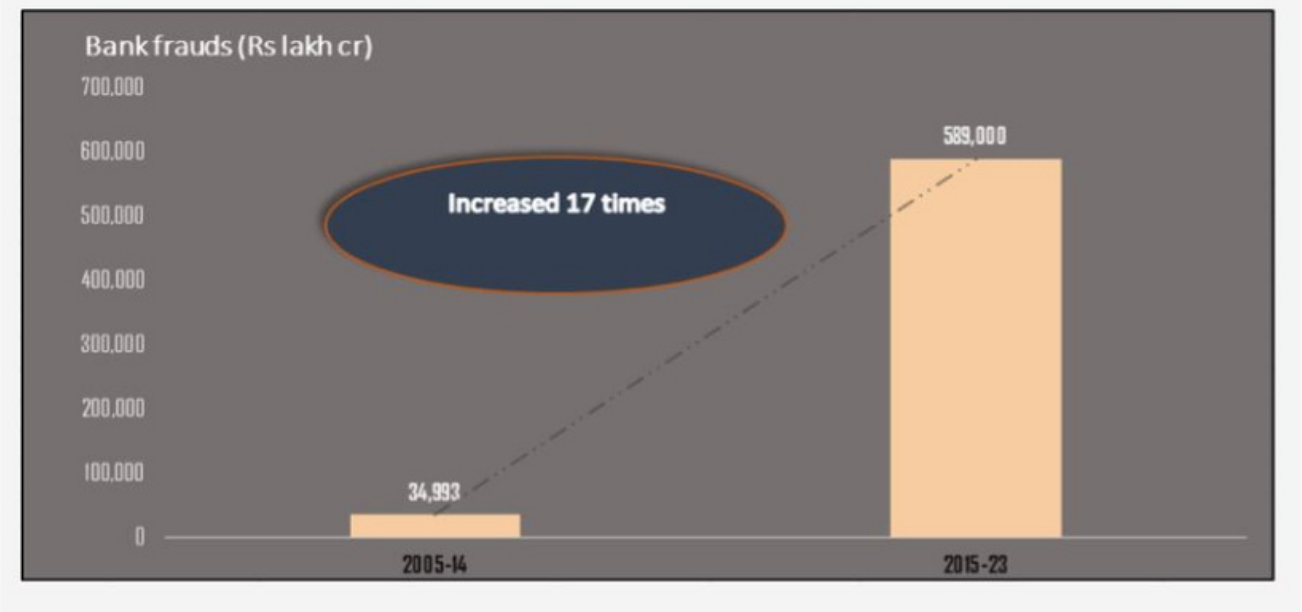

वास्तविकता

- **विजय माल्ल्या** जिन पर 10000 करोड़ रुपये का बकाया था, उन्होंने 2016 में देश छोड़ दिया। वित्त मंत्री ने वादा किया कि उन्हें वापस लाया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के साथ अच्छे संबंध होने के उनके दावों के बावजूद, यह अभी तक क्यों नहीं हुआ?

- क्या 11400 करोड़ की लूट, **नीरव मोदी, मेहर चौकसी और पीएनबी घोटाला** श्री मोदी के कार्यकाल में नहीं हुआ? अब तक क्या कार्रवाई हुई?

- **विनसम डायमंड्स के जतिन मेहता** ने 2014 में देश छोड़ दिया जब उन पर यहां के बैंकों का 7000 करोड़ कर्ज है। वह और उसका परिवार अभी भी विदेश में हैं, ठाठ और धूमधाम से रह रहे हैं। अखबारों ने बताया कि वह श्री गौतम अडानी के करीबी हैं।.

- **एबीजी शिपयार्ड के ऋषि कमलेश अग्रवाल** ने बैंकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है। 22842 करोड़ और धोखाधड़ी की सूचना 2019 में दी गई थी लेकिन कुछ खास नहीं हुआ।

- **कनिश गोल्ड प्रा. लिमिटेड** ने 2017 में बैंकों से 824 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

- **गुजरात स्थित स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड** ने 2017 में आंध्रा बैंक के प्रमुख कंसोर्टियम से 8100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

- **रोटोमैक पेन के विक्रम कोठारी पर 2919 करोड़ रुपये** का बकाया था जब उन्हें 2018 में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई, और वह अब नहीं रहे। धोखाधड़ी की रिपोर्ट 2015 में की गई थी।

- **वीडियोकॉन** धोखाधड़ी में आईसीआईसीआई ने कंपनी को 3250 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था और आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर शामिल थीं। धोखाधड़ी का खुलासा होने तक वह पीएम के साथ विदेश दौरों पर जाने वाले ग्रुप के साथ थीं।

- **आरपी इंफो सिस्टम धोखाधड़ी 2018** में सामने आई और इसमें शामिल राशि 515.15 करोड़ रुपये है।

- 2018 में सामने आए **एयरसेल धोखाधड़ी** में इसके संस्थापक सी. शिवशंकरन ने अकेले आईडीबीआई को 600 करोड़ रुपये का चूना लगाया है और मजे से विदेश में रह रहे हैं।

हाइलाइट

- **कोई सोच सकता है कि अति-अमीरों के खराब ऋणों के कारण बढ़ता एनपीए आम लोगों को कैसे प्रभावित करता है?** खैर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह गरीबों के लिए ऋण की उपलब्धता और उच्च ब्याज दरों को भी प्रभावित करता है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एनपीए का खामियाजा भुगतना पड़ता है।** एनपीए समस्या की गंभीरता का खामियाजा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भुगतना पड़ा। जबकि 2000 के दशक के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए अनुपात निजी बैंकों की तुलना में कम रहा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2010 के दशक के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की और एनपीए अनुपात को ऐसे स्तर पर दर्ज किया जो कि निजी बैंक से 6% अधिक है। इसलिए कॉरपोरेट और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। मंत्र है मुनाफ़े का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण।

- **कॉरपोरेट्स को अंधाधुंध ऋण देने का भुगतान कौन करता है?** एनपीए में तेज वृद्धि 2010 से प्रारम्भ हुए दशक में हुई जिसके दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध मुनाफे में गिरावट की कीमत पर हुई है। उल्लेखनीय बात यह है कि इस अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने परिचालन लाभ में वृद्धि के बावजूद घाटा दर्ज किया। इसका कारण एनपीए का बढ़ना था।
- **बढ़ते एनपीए के लिए गरीब सबसे कम जिम्मेदार हैं।** ऐतिहासिक रूप से, बैंकों के एनपीए में मुख्य योगदानकर्ता प्राथमिकता क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि बैंकों को कृषि और एमएसएमई को ऋण देना आवश्यक होता है। 1990 और 2000 के दशक तक यही चलन था। 2010 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए में गैर-प्राथमिकता क्षेत्र की हिस्सेदारी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में एनपीए की वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक है। जबकि 2000 के दशक के दौरान गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में पीएसबी के एनपीए का लगभग 50 प्रतिशत शामिल था, 2019 तक इसकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गई। यह हमारी आर्थिक नीति की प्राथमिकताओं में बदलाव को भी दर्शाता है।

- **एनपीए का व्यापार चक्र से कोई लेना-देना नहीं है।** कोई यह तर्क दे सकता है कि उच्च एनपीए निवेश का प्रतिबिंब है जो अंततः उत्पादन बढ़ने पर फल देगा। लेकिन 2013 के बाद से हमने उत्पादन वृद्धि दर में वृद्धि के बावजूद एनपीए में उछाल देखा है। इसलिए एनपीए का व्यवसाय चक्र से कोई लेना-देना नहीं है, इसका संबंध सरकारी नीति से है जो बड़े व्यवसाय के लिए अनुकूल है, और छोटे व्यवसाय का समर्थन करने से कतराती है।

- **एनपीए को बड़ी मछलियां चला रही हैं।** यह बड़े कॉरपोरेट थे जिन्होंने हाल की अवधि के दौरान अपने एनपीए अनुपात में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की। छोटी और मध्यम फर्मों और सूक्ष्म और लघु फर्मों के लिए, एनपीए अनुपात बड़े कॉरपोरेट्स की तुलना में काफी निचले स्तर पर रहा।

- **अत्यधिक अमीरों द्वारा उत्पन्न एनपीए गरीबों के लिए उपलब्ध ऋण की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है।** उच्च एनपीए के कारण बैंकों को होने वाले घाटे से बैंकों की ऋण वितरण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण वितरण में अपनी हिस्सेदारी में भारी गिरावट दर्ज की। बढ़ते एनपीए की अवधि के दौरान पीएसबी एमएसएमई की ऋण आवश्यकता के कम अनुपात को पूरा कर सकते हैं। तो यह गरीब ही हैं जो अमीरों के बुरे ऋणों के कारण होने वाली क्रेडिट राशनिंग का खामियाज़ा भुगत रहे हैं।

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल राइट-ऑफ 1,72,800 करोड़ रुपये है, **जो 2023-24 में नरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा को आवंटित राशि से काफी अधिक है।**

- बालासोर में दुखद ट्रेन दुर्घटना, जिसमें कम से कम 292 लोगों की मौत होगई, ने सुरक्षा पर खर्च के सवाल को सामने ला दिया। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैक के नवीनीकरण के लिए आवश्यक धन की संयुक्त कमी 103,395 करोड़ रुपये है। तुलनात्मक रूप से, उस वर्ष अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डालने की राशि **133,945 करोड़** रुपये थी।

- **बट्टे खाते में डालने से बैंकिंग प्रणाली अस्थिर हो सकती है:** यह मध्यम वर्ग के जमाकर्ता हैं जिनकी जमा राशि का उपयोग छोटी वसूली के साथ ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए किया जाएगा। यह विनम्र जमाकर्ता हैं जो लागत वहन करेंगे क्योंकि बैंक उन पर बोझ डाल देगा। उन्हें अपनी जमा राशि पर कम ब्याज दर मिलेगी, उन्हें कॉरपोरेट्स की तुलना में अपने ऋण के लिए अधिक ब्याज दर का भुगतान करना होगा, और उन्हें अधिक बैंक शुल्क का भुगतान करना होगा। बैंक स्टाफिंग में कमी करके अपनी ओवरहेड लागत को कम करके घाटे की भरपाई करने की भी कोशिश करेंगे।इस तरह के बट्टे खाते में डालने से अपराधियों को एक बार फिर ऋण लेने का मौका मिल जाएगा! जैसे-जैसे उनका डेटा साफ़ होगा, उनकी रेटिंग में सुधार होगा। स्वाभाविक रूप से, अच्छे उधारकर्ता जो तुरंत भुगतान कर रहे हैं वे चूक करना शुरू कर देंगे। इसका असर बैंकों पर पड़ेगा।उन उधारकर्ताओं को छोड़कर, जिन्होंने मजबूत संपार्श्विक दिया है, अन्य लोग चूक करेंगे और बट्टे खाते में डालने की उम्मीद करेंगे।

- 2018 में, यह बताया गया कि **5,600 विलफुल डिफॉल्टर्स में से 15% गुजरात से थे.**

- एबीजी शिपयार्ड (ऋषि अग्रवाल), विनसम डायमंड्स (जतिन मेहता), और कई अन्य विलफुल डिफॉल्टर सत्ता के गलियारों के करीब हैं। कुछ पहले से ही विदेश में हैं।

बाकी रिपोर्ट कार्ड केलिए: https://www.fanindia.net/indian-economy/balance-sheet-of-a-decade/